



सांध्य दैनिक 4PM



एक सिंघासन महज मखमल से ढकी एक बेंच है।
-नेपोलियन बोनापार्ट

मूल्य ₹ 3/-

जिद...सच की

www.4pm.co.in | www.facebook.com/4pmnewsnetwork | @Editor_SanjayS | YouTube | 4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 12 ● अंक 153 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शुक्रवार 10 जुलाई, 2026

श्रेयस की कप्तानी में लगातार दूसरी सीरीज... 7 मंत्रियों को हटाने वाले बिल को... 3 बूथ स्तर पर सपा और होगी... 2

मेरठ एसएसपी थाप्पड़ कांड की गुंज से गरमाई राजनीति

एनएचआरसी ने जारी किया नोटिस देना होगा जवाब

» डैमेज कंट्रोल करने उतरी मायावती, राकेश टिकैत भड़के अखिलेश यादव ने सुनाई खरी खोटी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। मेरठ में पुलिस वैन के भीतर हिरासत में बंद युवक को पुलिस अधिकारी द्वारा थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ चुका है और राजनीति चरम पर। सपा समेत दूसरी राजनीतिक दलों ने इस कांड पर आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना के संदर्भ में नोटिस जारी कर मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। अब इन थप्पड़ों का जवाब देने के लिए यूपी गृह सचिव और डीजीपी को आयोग के सामने पेशी देनी होगी।

सवाल सिर्फ घटनाओं का नहीं है सवाल अब उस मानसिकता का बन गया है जो बार-बार पुलिस व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर रही है। कभी थाने में फरियादी की सुनवाई पर सवाल उठते हैं तो कभी हिरासत में पुलिसिया व्यवहार पर तो कभी वहीं की गरिमा पर। लगातार जवाबदेही का डर कमजोर पड़ता जा रहा है? और कार्रवाई का भरोसा इतना कमजोर हो गया है कि कुछ अधिकारियों को लगता है कि कैमरे बंद हो जाएं तो सब कुछ सामान्य है? मेरठ की घटना ने पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या कानून के राज में ऐसा संभव है कि पुलिस वैन में पुलिस द्वारा पकड़ कर बिठाये गये व्यक्ति को कैमरों के सामने कूट दिया जाए। पकड़ा गया व्यक्ति कथित तौर इतना नर्वस हो जाए कि वैन में ही अपनी जान देने की कोशिश करें। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर जबर्दस्त उबाल है। लोग बात कर रहे हैं कि पुलिस कैमरे के सामने जब यह कर सकती है तो कैमरे के पीछे क्या नहीं कर सकती।



पुलिस अभिरक्षा में हाथ उठाना तानाशाही

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए पुलिस के आचरण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि घटना कैमरे के सामने घटित हुई है। यह कोई मामूली घटना नहीं है। पुलिस बेअंदाज है और अब उसकी आदत सी हो गयी है। घटना पर कार्रवाई हो वरना समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने सबसे कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस की सुरक्षा में बैठे व्यक्ति पर हाथ उठाना तानाशाही है। उनका कहना था कि कानून यदि आम नागरिक पर लागू होता है तो वहीं पहनने वाले अधिकारी भी उससे ऊपर नहीं हो सकते।



एसपी नहीं गुंडा है..दलित विरोधी है : गौतम

उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने एसपी अविनाश पांडेय के थप्पड़कांड पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो एसपी नहीं गुंडा है..दलित विरोधी है..मुस्लिम विरोधी है और सविधान विरोधी है। उन्होंने कहा कि रवि गौतम दलित है इसलिए वो थप्पड़ मार रहा है। इस एसपी के अंदर नाफरत भरी हुई है। इस एसपी को तुरंत



सस्पेंड किया जाना चाहिए और गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस

मुद्दे को लेकर सड़क पर जाएगी। यह वहीं अधिकारी है जिसने कहा था कि ईंट पर जो नमाज पढ़ने सड़क पर आएगा, उसको बंद करूंगा, उस पर मुकदमा दर्ज करूंगा और पासपोर्ट भी रद्द करूंगा। यह वहीं अधिकारी है जिसने फिल्म धुरंधर को दो सिनेमा हॉल बुक करके चारों ओर को दिखाया था। जो हिंदू-मुसलमान करने वाली फिल्म है।

बसपा सुप्रीमो बोली- नहीं मिलता न्याय

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा घटना के संदर्भ में बयान जारी करते हुए कहा है कि ऐसे तरीकों से पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता बल्कि उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलितों, वंचितों और उपेक्षित समाज को संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ राजनीतिक शक्ति हासिल करने का रास्ता दिखाया था। बाबा साहब का स्पष्ट संदेश था कि अन्याय और अत्याचार के



खिलाफ संघर्ष कानून के दायरे में रहकर किया जाए। यदि निचली अदालत से न्याय न मिले तो उच्च अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाए। उन्होंने कहा कि मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज, हरदोई

और देश के अन्य हिस्सों में जिस प्रकार की घटनाओं के बाद लोगों को उकसाकर आंदोलन कराए जा रहे हैं, उससे वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलने की संभावना कमजोर होती है। इसके बजाय कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रीढ़ी संकने का प्रयास करते हैं। पहले माहौल को हिंसा, धरना-प्रदर्शन और अशांति से बिगाड़ा जाता है और बाद में उनके नेता घटनास्थल पर पहुंचकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं।

आयोग का डीजीपी को नोटिस अब क्या करेगी पुलिस

शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज की घटना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गई है। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियंका कानूनगो कर रहे हैं ने डॉ. अंबेडकर जन कल्याण समिति की ओर से दी गई शिकायत पर सज्जन लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेरठ में एक शांतिपूर्ण जन प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बिना किसी

उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज किया। शिकायत के मुताबिक यह प्रदर्शन एक हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। आयोग है कि पुलिस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आई हैं। आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें पूछा गया है कि पुलिस को बल प्रयोग की जरूरत क्यों पड़ी। प्रदर्शनकारियों को कितनी और कैसी चोटें आईं। पुलिस कार्रवाई का आधार क्या था और घायलों को क्या विकराल सहायता उपलब्ध कराई गई।

बूथ स्तर पर सपा और होगी मजबूत

नेकां करेगा जंतर मंतर पर प्रदर्शन

» हर बूथ पर 50 नए सदस्य जोड़ेगी सपा

» अखिलेश यादव ने प्लान बीजेपी को घेरने की तैयारी

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी ताकत सहेजनी शुरू कर दी है। जहां पार्टी राममंदिर चोरी व पेपर लीक के मुद्दों को जोर-शोर से उठाने की तैयारी कर रही है वहीं अब एक नया मिशन-50 प्लान पर भी काम कर रही है। जिसके तहत सपा हर बूथ पर कम से कम 50 नए सदस्यों को जोड़ेगी।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हैं। एक तरफ सपा अपने पीडीए फॉर्मूले को जमीन पर मजबूत करने में जुटी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बूथ स्तर पर अपनी ताकत को और बढ़ाने की तैयारी है ताकि आगामी चुनाव में जीत को सुनिश्चित किया जा सके।

समाजवादी पार्टी के मिशन-50 प्लान



में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हर मतदान बूथ पर 50 नए सदस्य को जोड़ने की योजना है। सपा का मानना है कि अगर हरेक बूथ पर अपने समर्थकों को संगठन से जोड़ा जाएगा तो 27 के चुनाव की लड़ाई को आसान हो जाएगी। इस प्लान के तहत सपा का फोकस उन सीटों पर खासतौर से है जहां पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर कम रहा था।

24 की तरह 27 में लेंगे सफलता

24 के लोकसभा चुनाव में सपा को यूपी में बड़ी कामयाबी मिली थी और सपा सबसे ज्यादा सांसद चुनाव प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। सपा इस सफलता को 27 के चुनाव में भी दोहराना चाहती है। सपा को लगता है कि अगर संगठन की ताकत को जमीन पर मजबूत किया जाए तो उन सीटों पर जीत हासिल की जा सकती है जहां मामूली वोटों के अंतर से पार्टी हार गई थी। साल 022 के चुनाव में यूपी में करीब 60 सीटें ऐसी थी, जहां जीत हार का अंतर 5000वोटों के आसपास था, अगर इन सीटों पर सक्रियता को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़े जाएं चुनाव परिणामों को बदला जा सकता है। मिशन-50के साथ सपा नए लोगों को जोड़ने के लिए घर-घर अभियान भी चलाएगी और लोगों से संपर्क करेगी जिससे वोटिंग के दिन उन्हें चुनाव प्रबंधन समेत दूसरी जिम्मेदारियां दी जा सकें।

सपा कार्यालय की नई होर्डिंग से बढ़ी सियासी हलचल



लखनऊ में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगी एक नई होर्डिंग राजनीतिक गलियाओं में चर्चा का विषय बन गई है। होर्डिंग में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ स्वामी मुकुंश आनंद की तस्वीर लगाई गई है। होर्डिंग पर प्रमुखता से सनातन ही समाजवाद है का संदेश लिखा गया है। इस होर्डिंग को लेकर राजनीतिक हलकों में विभिन्न तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, इस संबंध में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

बूथ स्तर से ही चुनाव प्रबंधन की राह होगी आसान

यूपी में करीब 1.77 लाख मतदाता बूथ केंद्र हैं। अगर इन सभी बूथों पर सपा 50-50 नए सदस्य बनाने में कामयाब हो जाती है तो इससे पार्टी का नेटवर्क काफी मजबूत हो जाएगा और चुनाव प्रबंधन की राह आसान हो

जाएगी। यही नहीं हाल ही में सपा डिजिटल एप के जरिए भी नए लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। सपा ने बूथ प्रभारी और बूथ प्रहरी एप शुरू किया है, जिससे नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है।

कांग्रेस ने बनाया वाराणसी के लिए प्लान

» घर-घर जाएंगे बूथ कार्यकर्ता

» यूपी विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति पर काम शुरू

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों की तरह कांग्रेस ने कमर कसना शुरू कर दिया। इसबार वी पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र के लिए नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। वाराणसी में कांग्रेस पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए काम शुरू कर दिया है।

पार्टी ने शहर के 100 वार्डों में बूथ प्रहरी तैनात करने का ऐलान किया है। ये कार्यकर्ता लोगों से सीधे संपर्क कर उनकी समस्याएं जानेंगे और पार्टी की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 100 वार्डों में बूथ प्रहरी तैनात करने का फैसला केवल संगठनात्मक कदम नहीं, बल्कि वाराणसी की विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की बढ़ती दावेदारी का भी संकेत है। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों का समीकरण किस दिशा में जाता है और कांग्रेस को वाराणसी में कितनी सीटें मिलती हैं।



संगठन विस्तार का अभियान भी शुरू

पार्टी नेताओं के मुताबिक, बूथ प्रहरी अभियान के साथ वाराणसी महानगर में व्यापक संगठन विस्तार अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जाएगी।

आठ विधानसभा सीटों पर गठबंधन की नजर

वाराणसी जिले में कुल आठ विधानसभा सीटें हैं। यहां इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वाराणसी में तीन से चार सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, हालांकि अंतिम फैसला गठबंधन के सीट बंटवारे के बाद ही होगा।

सक्रिय कार्यकर्ताओं को बूथ प्रहरी बनाया जाएगा : राघवेंद्र

कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि पार्टी काशी के हर नागरिक तक पहुंचना चाहती है। इसी उद्देश्य से जिम्मेदार और सक्रिय कार्यकर्ताओं को बूथ प्रहरी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बूथ किसी भी लोकतांत्रिक

व्यवस्था की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। चौबे ने कहा- यदि बूथ मजबूत होगा तो संगठन भी मजबूत होगा और जनता की आवाज पहले से अधिक मजबूती के साथ उठाई जा सकेगी।

पेट्रोल की कीमत 82 रुपये हो : केजरीवाल

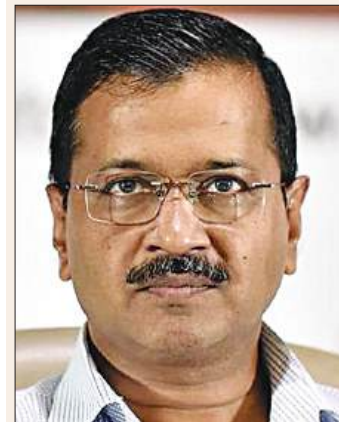
» आप संयोजक ने सरकार से की मांग

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि पिछले एक दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का फायदा ग्राहकों को नहीं मिला है। पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने मांग की कि पेट्रोल की कीमत मौजूदा 102 प्रति लीटर के बजाय 82 प्रति लीटर होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह तेल मार्केटिंग कंपनियों को नाजायज मुनाफा कमाने दे रही है।

केजरीवाल ने कहा कि पेट्रोल 102 प्रति लीटर के बजाय 82 प्रति लीटर मिलना चाहिए और डीजल की कीमतें भी कम होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि कच्चे तेल की कम कीमतों का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया जाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 14 के बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कई बार गिरी हैं, लेकिन इसका असर पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर नहीं दिखा। उन्होंने पूछा कि 14 से अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम से कम छह बार घटी हैं, लेकिन देश में पेट्रोल की कीमतें उस हिसाब से कम नहीं की गईं। इन सालों में जो भारी मुनाफा

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के दोषियों को सजा दिलाने के लिए देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाएगी आप



नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पार्टी अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी से जुड़े विवाद में शामिल दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर एक देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी। उन्होंने लोगों से इस मामले में एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर इस कथित चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दिलाया हर सनातनी का कर्तव्य है। इस अभियान के तहत हर नागरिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित एक पत्र पर हस्ताक्षर करके उनसे अपील करेगा।

कमाया गया, उसका क्या हुआ? केजरीवाल ने तर्क दिया कि ईंधन की कीमतें कम करने से महंगाई का दबाव कम होगा और परिवारों व व्यवसायों, दोनों पर वित्तीय बोझ भी घटेगा। उन्होंने केंद्र पर यह आरोप भी लगाया कि वह तेल कंपनियों को ईंधन की कीमतें कृत्रिम रूप से ऊंची बनाए रखने की अनुमति दे रहा है, जबकि उन्हें सस्ते कच्चे तेल से होने वाले लाभ का फायदा जनता तक पहुंचाना चाहिए। उनके ये बयान केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के उस संकेत के कुछ दिनों बाद आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें

चार महीने के निचले स्तर पर आने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कटौती की संभावना नहीं है। मंत्री के अनुसार, सरकारी रिफाइनर अभी भी उस कच्चे तेल को प्रोसेस कर रहे हैं जिसे वेस्ट एशिया में संघर्ष के चरम पर ऊंची कीमतों पर खरीदा गया था। संघर्ष शुरू होने के दो महीने से भी अधिक समय बाद, मई के दूसरे भाग में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 7.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन यह बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की लागत में हुई वृद्धि से कम थी, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को बोझ का कुछ हिस्सा उठाना पड़ा।



मैं चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा हूं : मुकेश सहनी

» यूपी पुलिस से वीआईपी प्रमुख की तीखी नोकझोंक, वीडियो वायरल

4पीएम न्यूज नेटवर्क

पटना। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी का उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी से टन गई है। दरअसल, दोनों के बीच फोन पर हुई तीखी बहस का का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

वीडियो में सहनी अपने प्रस्तावित उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर नाराजगी जताते हुए पुलिस अधिकारी से तीखे अंदाज में बात करते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। यह बातचीत उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में उनके प्रस्तावित रात्रि

मुझे यूपी आने से रोकिएगा

वीडियो में देखा जा सकता है कि बातचीत के दौरान सहनी का स्वर और तीखा हो जाता है। वह कहते हैं, मुझे यूपी आने से रोकिएगा, लोगों से मिलने नहीं दीजिएगा। क्या जन्मदिन या शादी में जाने के लिए भी आपसे अनुमति लेकर जाऊंगा? जब पुलिस अधिकारी उनकी भाषा पर आपत्ति जताते हैं तो सहनी जवाब देते हैं, मैंने भाषा में क्या गलत कहा है? आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और मैं भी सरकार में रह चुका हूं। मेरे हाथ में सविधान है। मुझे देश में कहीं भी जाने का अधिकार है।

प्रवास को लेकर है।

पुलिस अधिकारी ने कार्यक्रम के लिए

प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता का जिक्र किया है, जिस पर मुकेश सहनी ने कड़ी आपत्ति जताई है। वायरल वीडियो में बातचीत की शुरुआत में मुकेश सहनी कहते हैं, नमस्कार, कल मेरा महाराजगंज में रात्रि प्रवास है।

मैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रुककर नेताओं और लोगों से मिल रहा हूं। कोई बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है। इस पर पुलिस अधिकारी की ओर से कथित तौर पर कहा जाता है कि ऐसे कार्यक्रम के लिए अनुमति आवश्यक है। जवाब में सहनी कहते हैं, किसी जिले या किसी राज्य में जाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती। जब कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, तब अनुमति लेंगे। यहां कोई कार्यक्रम नहीं है।

मंत्रियों को हटाने वाले बिल को लेकर बड़ी तकरार

भाजपा ने कहा- भ्रष्टाचार को अधिकार समझता है विपक्ष

कांग्रेस बोली- मोदी सरकार के इस विधेयक का करेंगे बहिष्कार

» बीजेपी ने विपक्षी दलों पर लगाये आरोप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को उनके पद से हटाने के प्रावधान वाले विधेयक को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है।

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह इस विधेयक का विरोध सिर्फ इसलिए कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे भ्रष्टाचार करने से नहीं रोका जाना चाहिए।

आम लोगों और नेताओं के लिए अलग मापदंड क्यों

बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों और आम नागरिकों के लिए एक समान मानक की वकालत की। अगर कोई आम आदमी जेल जाता है, तो क्या उसे एक दिन भी अपनी नौकरी जारी रखने की इजाजत मिलेगी? उसे तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। तो फिर निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकारी पदों पर बैठे लोगों के लिए अलग कानूनी पैमाना क्यों होना चाहिए?



संविधान संशोधन विधेयक विरोधियों को राजनीतिक रूप से परेशान करने के मकसद से लाया गया : जयराम

बीजेपी की यह टिप्पणी कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश के इस बयान के एक दिन बाद आई है कि यह संविधान संशोधन विधेयक विरोधियों को राजनीतिक रूप से परेशान करने के मकसद से लाया गया है और उनकी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। बीजेपी के

राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि प्रस्तावित कानून का मकसद कार्यकारी पदों पर बैठे लोगों के लिए जवाबदेही के समान मानक तय करना



है। बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने एक वीडियो संदेश में कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्हें लगता है कि सिर्फ उन्हें को सब कुछ पाने का हक है। उन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार करना उनका अधिकार है। वे भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं और अगर कोई उन्हें पकड़ ले, तो वे उत्पीड़न का रोना रोने लगते हैं।

संयुक्त समिति के पास भेजा जा चुका विधेयक

उन्होंने कहा कि विधेयक को पहले ही संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जा चुका है और विपक्षी दलों को सीधे इसका विरोध करने के बजाय समिति की सिफारिशों का इंतजार करना चाहिए। समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने दें। लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और मर्यादा नहीं चाहते? क्या उन्हें लगता है कि उन्हें अपराध और भ्रष्टाचार करने की छूट है?

राजनीतिक संस्कृति को बदलने की योजना

कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस राजनीतिक संस्कृति को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि उनके लिए लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए चुनी गई सरकार नहीं होनी चाहिए। उनके लिए अपराधियों की

अपराधियों द्वारा, अपराधियों के लिए चुनी गई सरकार होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, संबंधित विधेयकों पर विचार कर रही संसदीय समिति 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है और इसे संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश कर सकती

अरविंद केजरीवाल पर चलाया तीर

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध को अपना अधिकार समझने की इस सोच को खत्म किया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए पूनावाला ने सवाल उठाया कि क्या कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री जेल से शासन चलाना जारी रख सकता है। उन्होंने

कहा कि संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि अगर कोई मुख्यमंत्री या सरकार का कोई पदाधिकारी जेल



जाता है, तो वह इस्तीफा नहीं देगा। हमने अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा देखा, जिन्होंने जेल में रहते हुए भी सरकार चलाना जारी रखा। क्या प्रशासनिक तौर पर ऐसा मुमकिन है? यह ईमानदारी का भी सवाल है। बीजेपी नेता ने विपक्षी दलों पर सार्वजनिक पद से इस्तीफे

के मुद्दे पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पहले तो वे (विपक्षी नेता) एक आरोप का संकेत भर मिलने पर लोगों से इस्तीफा मांगते थे। अब जब अदालत उन्हें एक के बाद एक मामलों में जेल भेज रही है, तो वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं।

राजस्थान में फिर जाटों की सियासत

» बेनीवाल-भाजपा के बीच टकराव

» कांग्रेस की चिंता बढ़ी

» तो क्या जाट वोट बैंक में लगेगी नई सेंध

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान की सियासत में जाट वोट बैंक एक बार फिर अहम मुद्दा बन गया है। भाजपा और हनुमान बेनीवाल के बीच जारी सियासी टकराव के बीच अब कांग्रेस के पारंपरिक जाट वोट पर भी असर पड़ने के आसार हैं।

राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और हनुमान बेनीवाल के बीच जारी तीखी बयानबाजी ने जाट राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। राजनीतिक हलकों में यह आकलन किया जा रहा है कि इस टकराव का सबसे बड़ा असर कांग्रेस के



गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर भी घमासान

इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का डॉ. किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के विवाद को लेकर दिया गया बयान भी राजनीतिक मायने रखता है। राजनीतिक विरोधियों का मानना है कि यह बयान जाट समाज के बीच सकारात्मक संदेश देने की रणनीति

का हिस्सा हो सकता है। वहीं हनुमान बेनीवाल पहले भी कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन की बात सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जाट वोट बैंक की दिशा राजस्थान की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है।

पारंपरिक जाट वोट बैंक पर पड़ सकता है। यदि बड़ी संख्या में जाट मतदाता

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) की ओर रुख करते हैं तो इसका सीधा

कांग्रेस की चुप्पी भी राजनीतिक चर्चा

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस की चुप्पी भी राजनीतिक चर्चा का विषय बनी रही। पार्टी ने न तो बेनीवाल के समर्थन में कोई खुला बयान दिया और न ही उनके विरोध में। इससे जाट समाज के भीतर यह सवाल भी उठ रहा है कि वर्षों से समर्थन मिलाने के बावजूद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख क्यों नहीं अपनाया।

राजनीतिक लाभ भाजपा को मिलने की संभावना जताई जा रही है।

50 से 60 विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव

राज्य में जाट समुदाय को सबसे प्रभावशाली राजनीतिक वर्गों में माना जाता है। अनुमानित रूप से 80 लाख से एक करोड़ के बीच आबादी वाला यह समुदाय शेखावाटी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर तथा भरतपुर के कुछ क्षेत्रों सहित करीब 50 से 60 विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव रखता है। लंबे समय तक जाट मतदाताओं का बड़ा वर्ग कांग्रेस के समर्थन में माना जाता रहा है और सत्ता परिवर्तन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में भाजपा से टकराव के दौरान हनुमान बेनीवाल को जाट समाज के एक बड़े वर्ग का समर्थन मिलता दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। यदि यह समर्थन चुनाव तक कायम रहता है तो कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग सकती है, जिससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

जिद... सच की

धर्मस्थलों में पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी तत्व

राम जिनको भारत के हर घर में पूजा जाता है। उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अयोध्या स्थित श्री रामलला मंदिर में दानपात्रों से धन चोरी की घटना ने पूरे देश ही नहीं सनातन को मानने वाले हर व्यक्ति को शर्मसार कर दिया है। यह केवल एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, धार्मिक संस्थानों की विश्वसनीयता और उनके प्रशासनिक प्रबंधन से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। हालांकि ट्रस्ट ने अपनी बैठक में ट्रस्ट आरोपियों को चलता कर दिया है। उनके खिलाफ पुलिस की कार्यवाही चल रही है। साथ ही पूरी व्यवस्था में सुधार की बात कही है। हालांकि ये सब ठीक है पर इस कुकृत्य से जिम्मेदारों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। धार्मिक संस्थाओं की पवित्रता केवल पूजा-पद्धति से नहीं, बल्कि उनके प्रशासनिक चरित्र से भी तय होती है। पारदर्शी व्यवस्था आस्था को मजबूत करती है, जबकि लापरवाही या अपारदर्शिता संदेह को जन्म देती है। इसलिए यह समय दोषारोपण का नहीं, बल्कि व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय बनाने का है।

इस मामले कई महान लोगों ने अपने वक्तव्यों से संदेश दिया कि आस्था के केंद्र भी जवाबदेही से ऊपर नहीं हो सकते। यदि किसी धार्मिक संस्थान में सुरक्षा या प्रशासनिक व्यवस्था में चूक होती है, तो उसे छिपाने के बजाय स्वीकार करना और सुधारना ही उसकी गरिमा को बढ़ाता है। राम मंदिर केवल एक भव्य निर्माण नहीं, बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना, विश्वास और लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का प्रतीक है। ऐसे संस्थान की प्रतिष्ठा उसकी ऊँची दीवारों या भव्य शिखरों से नहीं, बल्कि उसके प्रबंधन की पारदर्शिता और नैतिकता से भी तय होती है। श्रद्धालु जब दानपात्र में धन डालता है, तो वह केवल रुपये नहीं देता, बल्कि अपना विश्वास भी सौंपता है। उस विश्वास की रक्षा करना प्रत्येक संबंधित संस्था और प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। यह स्पष्ट संदेश है कि दोषियों की पहचान हो, निष्पक्ष जांच हो और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई हो। इससे यह भी संकेत मिलता है कि धार्मिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता आवश्यक है, न कि मौन। इस घटना को राजनीतिक चरम से देखने की जल्दबाजी भी उचित नहीं होगी। किसी भी सार्वजनिक वक्तव्य की व्याख्या उसके शब्दों और आशय के आधार पर होनी चाहिए, न कि पूर्वाग्रहों के आधार पर। यदि वक्तव्य का केंद्र बिंदु आस्था की रक्षा, जवाबदेही और निष्पक्ष जांच है, तो उसी संदर्भ में उसका मूल्यांकन होना चाहिए।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

लिपुलेख पर भारत की कूटनीतिक कामयाबी

पुष्परंजन

झांग माओमिंग काठमांडू स्थित चीन के राजदूत हैं। 24 जून को काठमांडू पोस्ट में उनका एक लेख 'मोर प्रैक्टिकल कॉन्फ्रेंशन' शीर्षक से छपा, जिसमें नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल की 14 से 17 जून की पेइचिंग यात्रा के हवाले से यह बताने की चेष्टा की गई, कि नेपाल को अब 'व्यावहारिक कूटनीति' पर ध्यान देना चाहिए। अब ये व्यावहारिक कूटनीति क्या बला है? नेपाल बफर स्टेट होने के नाते चाइना कार्ड आये दिन खेलता था, नई दिल्ली तक से सौदेबाजी हो जाती थी। अब चीन ने नेपाली नेतृत्व को ये समझा दिया, कि आप बदलिये और व्यावहारिक होइये। लिपुलेख मुद्दे पर चीन और भारत ने नेपाल को जिस तरह चुप करा दिया है, उस पर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियां, राजावादी और नेपाली कांग्रेस के नेता तक हैरान हैं।

चीनी राजदूत झांग माओमिंग बताते हैं, नेपाली विदेश मंत्री खनाल ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्यों और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की। नेपाली पक्ष ने फिर से कहा कि ताइवान का सवाल और शिजांग से जुड़े मुद्दे चीन के अंदरूनी मामले हैं। नेपाल पूरी तरह से वन-चाइना सिद्धांत का पालन करता है, किसी भी ताकत को नेपाली इलाके का इस्तेमाल चीन के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करने देगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए, कि हाई-क्वालिटी 'बेल्ट एंड रोड सहयोग' को आगे बढ़ाएंगे। वहां चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। पहला, क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और हवाई संपर्कों के विकास में तेजी लाकर दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को दुरुस्त करना, जिससे नागरिक के आपसी संपर्क और अधोसंरचना में सुधार हो। दूसरा, बिजली, पावर ग्रिड और क्लीन एनर्जी में सहयोग बढ़ाकर सहयोग को गहरा करना, और तीसरा, उभयपक्षीय व्यापार संरचना को ऑप्टिमाइज करके निवेश

को बढ़ाना। चीनी कंपनियों से दोस्ताना माहौल बनाना। चौथा, शिक्षा, युवा, लोकल गवर्नमेंट और मीडिया में सहयोग बढ़ाना है, ताकि दोनों देशों की जनता एक-दूसरे को समझे।

यह गौर करने वाली बात है, कि नेपाली विदेशमंत्री शिशिर खनाल ने एक बार भी लिपुलेख-लिम्पियाधरा मार्ग से भारत-चीन व्यापार का मुद्दा नहीं उठाया। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेन्द्र लाल नेपाली बोलते हैं, 'यह सरकार डीप स्टेट वाले चला रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया है। यह नेपाल के

गति मिलने की उम्मीद है। लिपुलेख से व्यापार मोदी कूटनीति की सफलता कही जाएगी। सत्तारूढ़, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने भी दिल्ली आने पर समझ चुके थे, कि लिपुलेख पर भारत से विवाद, उभयपक्षीय संबंधों को और बिगाड़ेगा, और इस मुद्दे पर चीन उनके साथ खड़ा नहीं है। लिपुलेख, रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण ट्राई-जंक्शन है जहां भारत, नेपाल, और चीन की सीमाएं मिलती हैं। यह क्षेत्र सदियों से कैलास मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है। 2020 में भारत द्वारा धारचुला से लिपुलेख तक एक सामरिक



भविष्य के लिए खतरनाक है।' उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत-चीन सीमा व्यापार छह वर्ष बाद 26 जून 2026 से शुरू हो गया। उस दिन 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश किया। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप-जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। व्यापारियों ने अपना सामान पहले ही लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों में पहुंचा दिया है। प्रशासन को 103 से अधिक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए थे, और जल्द ही 25 व्यापारियों के दूसरे दल को भी व्यापार पास जारी किए जाएंगे। सामान दुलाई के लिए नाभीढांग के पास खच्चरों और घोड़ों की व्यवस्था की गई है। छह वर्ष बाद इस मार्ग से व्यापार बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई

सड़क का उद्घाटन करने पर विवाद काफी बढ़ गया। नेपाल ने आरोप लगाया, कि भारत ने उसकी सहमति के बिना उसके इलाके में सड़क का निर्माण किया।

इस सड़क निर्माण के विरोध में जून 2020 में नेपाल सरकार ने एक नया 'चूचे नक्शा' जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधरा को आधिकारिक तौर पर नेपाली भूभाग के रूप में शामिल किया गया। भारत इन दावों को ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत, अनुचित और एकतरफा मानता है। भारत का हमेशा से यही रुख रहा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधरा ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। इस मार्ग से व्यापार पेइचिंग ने स्वीकार किया है, जिससे साबित होता है कि लिपुलेख-लिम्पियाधरा भारत का ही पार्ट है। इसे भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत माननी चाहिए।

प्रो. पूर्णदु रंजन

मानसून के आगमन से पहले के दिनों में कदम बाहर निकालते ही हवा दमघोंटू महसूस होने लगती है। हवा सिर्फ गर्म नहीं है; इसमें एक ऐसा भारीपन, सघनता और ठहराव है मानो वायुमंडल का वजन बढ़ गया हो और हमारी त्वचा को दबा रहा हो। दोपहर होते-होते, सामान्य वेदर ऐप हवा का तापमान 39 या 40 डिग्री सेल्सियस दिखा सकता है, जो देखने में शायद सहनीय लगे। लेकिन शरीर को यह तापमान 49-50 डिग्री सेल्सियस के समान महसूस होता है। यह कोई वहम नहीं; 'हीट इंडेक्स' की वह डरावनी वास्तविक तस्वीर है जो साबित करती है कि हमारे पारंपरिक मौसम वैज्ञानिक पैमाने इंसानी शरीर के जलवायु संकट को मापने में बुनियादी रूप से विफल हो रहे हैं। दशकों से, भारत में सार्वजनिक प्रशासन और आपातकालीन हीट प्रोटोकॉल केवल एक ही आंकड़े से संचालित हो रहे हैं एक साधारण थर्मामीटर पर आंका जाने वाला 'ड्राई-बल्ब' तापमान।

यदि राजस्थान के सूखे मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री से. छू जाता है, तो उसे आधिकारिक तौर पर 'लू' (हीटवेव) घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मौजूदा उमस भरी गर्मी कहीं अधिक कपटपूर्ण थर्मोडायनामिक सिद्धांत पर काम कर रही है। मानसून की देरी के कारण दक्षिण-पश्चिमी हवाएं आती हैं, तो ह्यूमिडिटी 60-70 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। मानव शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीने का वाष्पीकरण करता है। त्वचा से पसीना वाष्पीकृत होता है जो अपने साथ शरीर की आंतरिक ऊष्मा को बाहर ले जाता है। बहरहाल, जब आसपास की हवा पहले से ही नमी से

महसूस होने वाला तापमान बने गर्मी का पैमाना



पूरी तरह संतुप्त हो-एक भीगे हुए स्पंज की तरह तो वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया ठप हो जाती है। शरीर का आंतरिक अनुकूलन तंत्र काम करना बंद कर देता है, और उसका तापमान घातक सीमाओं की ओर बढ़ने लगता है। यह स्थिति हमें 'वेट-बल्ब तापमान' की चरम सीमा के खतरनाक रूप से करीब ले आती है जो कि मानव शरीर द्वारा झेली जा सकने वाली संयुक्त गर्मी और आर्द्रता की अंतिम सीमा है।

अमेरिका के 'पेंसिल्वेनिया स्टेट हीट प्रोजेक्ट' के हालिया चिकित्सा अनुसंधान के मुताबिक, मानव शरीर मात्र 31 डिग्री सेल्सियस के वेट-बल्ब स्तर पर ही अपने आंतरिक तापमान पर नियंत्रण खोना शुरू कर देता है। इस उमस भरे प्रहार का सबसे बड़ा खतरा है कि यह हमारी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए संरचनात्मक रूप से अदृश्य बना रहता है। जून के अंत और अब जुलाई के शुरू में महानगरों में 'हीट इंडेक्स' 51 से 53 डिग्री पार कर गया। ड्राई-बल्ब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) कठोर नियामक मानदंडों

के कारण अक्सर आधिकारिक तौर पर हीटवेव की घोषणा नहीं कर सका। इससे श्रमिकों की परेशानी की अनदेखी हुई। 'लू' घोषित नहीं होती, इसलिए श्रम प्रवर्तन एजेंसियां निर्माण श्रमिकों, डिलीवरी बॉयज और कृषि मजदूरों के लिए दोपहर के विश्राम की अवधि निर्धारित नहीं करतीं। इन कामकाजी लोगों को 50 डिग्री की दहकती भट्टी जैसी स्थिति में खटना पड़ता है। वहीं 'हीटस्ट्रोक' के मामलों में स्वास्थ्य प्रणालियां अक्सर उमस के दौर में हताहतों की संख्या कम आंकती हैं। यदि भारत को ऐसे युग में जीवित रहना है जहां 'महसूस होने वाला' तापमान नियमित रूप से 50 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू रहा हो, तो हमारी जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को क्रांतिकारी बदलाव से गुजरना होगा। आईएमडी और राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनियों, स्कूलों की छुट्टियों और श्रम नियमों के निर्धारण के कानूनी पैमाने के रूप में ड्राई-बल्ब थर्मामीटर को हटाकर आधिकारिक तौर पर 'कंपोजिट हीट रिस्क इंडेक्स' (संयुक्त ऊष्मा जोखिम सूचकांक) को लागू करना चाहिए। 65 फीसदी आर्द्रता

वाले 40 डिग्री सेल्सियस के दिन को भी प्रशासनिक रूप से उतनी ही गंभीरता मिले, जितनी 47 डिग्री सेल्सियस वाले शुष्क दोपहर को। इस दमघोंटू गर्मी के प्रति आम उपभोक्ताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया अधिक से अधिक निजी हाई-पावर सप्लिट एसी खरीदने की होती है। लाखों निजी एसी बेहद गर्म हवा सीधे तंग सड़कों पर छोड़ते हैं, जिससे 'अर्बन हीट आइलैंड' का प्रभाव गहरा हो जाता है। यह शहरी गरीबों के लिए सार्वजनिक रास्तों को 'थर्मल डेथ ट्रेप' बना देता है जो एसी नहीं खरीद सकते।

भारत को इसके वैश्विक संरचनात्मक विकल्पों की ओर देखना चाहिए, जैसे फ्रांस का भूमिगत 'क्लाइमस्पेस' नेटवर्क या गुजरात के 'गिफ्ट सिटी' में हमारा अपना स्वदेशी मॉडल। हमें कूलिंग को एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक यूटिलिटी के रूप में अपनाना होगा—यानी ऐसे 'डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम' जो इंसुलेटेड पाइपों के जरिए ठंडे पानी को पूरे वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में घुमाकर ठंडा रख सकें। भवन नियमों को शीशे और कंक्रीट के उन ढांचों से दूर हटना होगा जो विशाल ग्रीनहाउस जाल की तरह काम करते हैं। 'ऊर्जा संरक्षण भवन कोड' लागू कर इमारतों में प्रकाश परावर्तित करने वाली ठंडी छतें, क्रॉस-वेंटिलेशन के रास्ते और खोखली इंसुलेटेड ईंटों का उपयोग अनिवार्य किया जाए। यह अंदरूनी तापमान को 5 डिग्री तक कम कर सकता है, जिससे रहने के लिए एसी पर निर्भरता कम हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन को सीधे नहीं, बल्कि विभिन्न कारकों को आपस में मिलाकर तेजी से प्रभावित कर रहा है। जब हवा का तापमान कुछ और कड़े और इंसान की त्वचा कुछ और महसूस करे।

वरियाली शरबत करेगा शरीर में पानी की कमी को पूरा

गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन और लू की समस्या आम हो जाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और चक्कर जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। ऐसे समय में शरीर को ठंडक और एनर्जी देने वाले प्राकृतिक पेय बहुत फायदेमंद होते हैं। गुजरात में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वरियाली शरबत एक ऐसा ही हेल्दी ड्रिंक है, जो न सिर्फ शरीर को ठंडा रखता है बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। वरियाली यानी सौंफ से बने वाला यह शरबत गर्मी में राहत देने का एक प्राकृतिक उपाय है। अगर आप गर्मी में हेल्दी और फेश रहना चाहते हैं, तो वरियाली शरबत को अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करें।

शरबत के फायदे

शरबत के फायदे

ये शरीर को तुरंत ठंडक पहुंचाता है और लू से बचाने में मदद करता है। सौंफ में मौजूद प्राकृतिक गुण शरीर के तापमान को संतुलित रखते हैं और डिहाइड्रेशन की समस्या को कम करते हैं। यह गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। ये शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और थकान व कमजोरी को दूर करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट

सामान

सौंफ (वरियाली), चीनी या गुड़, नींबू, काला नमक, टंडा पानी, पुदीना



शरीर की इम्युनिटी को भी मजबूत बनाते हैं।

विधि

इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 से 3 बड़े चम्मच सौंफ लें और उसे साफ पानी से अच्छे से धो लें। अब इसे 4 से 5 घंटे या रातभर पानी में भिगोकर रख दें, ताकि सौंफ के सभी पोषक तत्व पानी में अच्छी तरह घुल जाएं। भीगी हुई सौंफ को

मिक्सर में डालकर थोड़ा सा पानी मिलाते हुए बारीक पीस लें। इसके बाद इस पेस्ट को एक बारीक छत्री या मलमल के कपड़े से छान लें,

ताकि इसका अर्क निकल आए। अब इस छने हुए रस में स्वादानुसार चीनी या गुड़ मिलाएं और अच्छे से

घोल लें। इसके बाद इसमें आधा नींबू का रस और एक चुटकी काला नमक डालें, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं। अब इसमें टंडा पानी मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। इसे फिज में टंडा करके या बर्फ डालकर सर्व करें।

पेट हो गया खराब तो तुरंत बनाएं सादी खिचड़ी

गर्मियों का मौसम अपने साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है, जिनमें सबसे आम है पेट खराब होना। तेज धूप, डिहाइड्रेशन, बाहर का खाना और अनियमित दिनचर्या पाचन तंत्र को कमजोर बना देते हैं। ऐसे में भूख कम लगना, पेट दर्द, गैस, उल्टी या दस्त जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इस स्थिति में भारी और मसालेदार खाना आपकी परेशानी को और बढ़ा सकता है। इसलिए डॉक्टर और आयुर्वेद दोनों ही हल्के, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन की सलाह देते हैं। इन्हीं में से एक है सादी खिचड़ी, जो न सिर्फ हल्की होती है, बल्कि शरीर को जरूरी पोषण भी देती है। खिचड़ी चावल और दाल से बनती है, जो आसानी से पच जाती है और पेट को आराम देती है। यह शरीर को एनर्जी देती है, डिहाइड्रेशन से बचाती है और पाचन तंत्र को धीरे-धीरे ठीक करने में मदद करती है। यहां जानिए सादी खिचड़ी के फायदे और इसे बनाने का आसान तरीका। दिन में 2-3 बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खिचड़ी खाएं। इसे गर्म और ताजा ही खाएं ताकि पेट को ज्यादा आराम मिले। साथ में दही या छाछ भी लिया जा सकता है।

सादी खिचड़ी



खिचड़ी क्यों है बेहतर विकल्प?

जब पेट खराब होता है, तो शरीर को ऐसा खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए। सादा खिचड़ी में कम मसाले होते हैं और यह पेट पर बिल्कुल हल्का पड़ता है। यह पाचन तंत्र को बिना ज्यादा मेहनत के ऊर्जा देता है।

विधि

एक कप चावल और आधा कप मूंग दाल लें। इन्हें अच्छे से धोकर प्रेशर कुकर में डालें। इसमें हल्दी, नमक और पर्याप्त पानी डालें। 3-4 सीटी आने तक पकाएं। चाहें तो थोड़ा सा घी ऊपर से डाल सकते हैं। खिचड़ी बनाते समय ज्यादा मसाले, तेल या मिर्च का इस्तेमाल न करें। बाहर का खाना और ठंडे पेय से बचें। पर्याप्त पानी पिएं और आराम करें ताकि जल्दी रिकवरी हो सके।

फायदे

सादा खिचड़ी शरीर को हाइड्रेट रखती है। पेट की सूजन कम करती है। खिचड़ी से कमजोरी दूर होती है। इसमें मौजूद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शरीर को ताकत देते हैं।



हंसना मना है

एक बार एक अंग्रेज ने इंडियन से कहा- 'आपके यहां किसी को गोरा, किसी को काला होता है। ऐसा क्यों?' भारतीय ने इसका जवाब देते हुए कहा- 'गधे एक ही रंग के होते हैं जबकि घोड़े रंग-बिरंगे होते हैं।'

पति- 'आज सवेरे शोव करने के पश्चात् मैं महसूस कर रहा था कि मेरी उम्र के दस साल कम हो गए।' पत्नी- 'क्या कहते हो! अगर इस स्पीड से प्रतिदिन आयु कम होती चली गई, तो एक हफ्ते

में आप गायब ही हो जाओगे।'

श्रीमान् जी का थोड़ा लड़का अपनी आयु के हिसाब से कुछ अधिक ही होशियार था। एक दिन घर आया तो उसके हाथ में लाइब्रेरी को एक पुस्तक थी- 'बच्चों का पालन-पोषण।' उसकी मां ने आश्चर्य से पूछा- 'क्यों मुझे, इस पुस्तक का आप क्या करोगे? मुझे ने जबाब दिया- 'मैं इसे पढ़कर ये जानना चाहता हूँ कि मेरा पालन-पोषण उचित ढंग से किया जा रहा है की नहीं।'

कहानी

कोयला और चंदन

चौधरी पहलवान का पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित हुआ था। जब उनका अंतिम समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा पास आ गया तो उन्होंने उससे कहा - देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले जरा तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठा कर ले लाओ। बेटे को पहले तो यह बड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब पिता का हुक्म है तो यह सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संयोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे आया देख पहलवान बोले- बेटा, अब इन दोनों चीजों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीजें नीचे फेंक दीं और हाथ धोने जाने लगा तो पहलवान बोले- जरा ठहरो बेटा। मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। बेटे ने हाथ दिखाए तो वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़ कर बोले, देखा तुमने। कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया। लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिख लगी रह गई। गलत लोगों की संगति ऐसी ही होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके न रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना।

7 अंतर खोजें



जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

<p>मेघ</p> <p>प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी। धनार्जन होगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। प्रमाद न करें। संपत्ति के लेनदेन में सावधानी रखें।</p>	<p>तुला</p> <p>यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल लाभ देंगे। भेंट आदि की प्राप्ति होगी। कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता रहेगी। व्यापार में उन्नति के योग हैं। सगे-संबंधी मिलेंगे।</p>
<p>वृषभ</p> <p>संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। बेरोजगारी दूर होगी। धन की आवक बनी रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य न करें। लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी।</p>	<p>वृश्चिक</p> <p>वाणी पर नियंत्रण रखें। अप्रत्याशित बड़े खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है, जोखिम न लें। अजनबी व्यक्ति पर विश्वास न करें।</p>
<p>मिथुन</p> <p>रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। किसी आन्दोलन में भाग लेने का मौका मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। पूंजी निवेश बढ़ेगा। प्रचार-प्रसार से दूर रहें।</p>	<p>धनु</p> <p>नई योजना बनेगी। नए अनुबंध होंगे। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है। परिवार की समस्याओं की चिंता रहेगी।</p>
<p>कर्क</p> <p>क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दुःखद समाचार मिल सकता है। चिंता बनी रहेगी। व्यापार-व्यवसाय में सावधानी रखें। वास्तविकता को महत्व दें।</p>	<p>मकर</p> <p>नए अनुबंधों का लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। पुष्प-परख रहेगी। रुके कार्य बनेंगे। जोखिम न लें। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। खानपान पर नियंत्रण रखें।</p>
<p>सिंह</p> <p>मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रु शांत रहेंगे। धनार्जन होगा। आज विशेष लाभ होने की संभावना है। व्यापार में कार्य का विस्तार होगा।</p>	<p>कुम्भ</p> <p>कोर्ट व कचहरी के काम निबटेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। तंत्र-मंत्र में रुचि रहेगी। धनार्जन होगा। प्रमाद न करें। सतान के कार्यों से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।</p>
<p>कन्या</p> <p>मेहनतों का आवागमन होगा। उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी। मान बढ़ेगा। जल्दबाजी न करें। जोखिम के कार्यों से दूर रहें। पराक्रम में वृद्धि होगी।</p>	<p>मीन</p> <p>वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। दूसरों की जमानत न लें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है।</p>

बॉलीवुड

मन की बात

प्रतिभा से पहले महिलाओं का रंग रूप देखता देखा जाता है : अंजली



अंजली आनंद इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'धमाल 4' को लेकर चर्चाओं में हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में बॉडी शेपिंग को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि 2026 में भी महिलाओं के रूप-रंग को लेकर होने वाली चर्चाएं उनके काम पर हावी रहती हैं। उन्होंने फिल्म धमाल 4 में अपनी भूमिका पर मिली प्रतिक्रिया और अपने वजन को लेकर हो रही ट्रोपिंग के बारे में बताया कि समाज आज भी महिलाओं की प्रतिभा को पहचानने से पहले उनके रूप-रंग को देखकर उनका आकलन करता है। अंजलि आनंद ने धमाल 4 के ट्रेलर पर मिली प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं हर चीज से अभिभूत हूँ। मुझे उम्मीद है कि सभी को फिल्म पसंद आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि इससे मुझे और भी अच्छे रोल मिलेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह निराशाजनक है कि महिला अभिनेत्रियों के बारे में चर्चाएं आज भी उनके काम के बजाय उनके वजन के इर्द-गिर्द घूमती हैं? इस पर अंजलि ने कहा कि यह समाज की मानसिकता को दर्शाता है। हां, और मुझे लगता है कि यह अभी भी हो रहा है, क्योंकि समाज अभी भी उसी सोच को दर्शाता है। समाज अभी भी मानता है और अभी भी मेरे काम से पहले मेरे वजन को देखा जाता है। इसलिए जब तक ऐसा होता रहेगा, तब तक मैं यह काम करती रहूंगी, यह साबित करने के लिए कि यह गलत है। महिलाओं के लिए बेहतर रोल लिखने के मामले में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मैं यही करने की कोशिश कर रही हूँ। जितने ज्यादा लोग मुझे देखेंगे, उनकी सोच उतनी ही खुलेगी। वे यह मानने लगेंगे कि वे इस एक्टर और इस रोल के लिए कुछ बेहतर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ जिसमें सिर्फ उनके शरीर का नहीं, बल्कि उनके हुनर का इस्तेमाल हो।

हिंदी कॉमेडी फिल्मों की दुनिया में राजपाल यादव और अक्षय कुमार ऐसे दो नाम हैं, जो दशकों से दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचते रहे हैं। भूल भुलैया और खट्टा मीठा से लेकर इस साल की सुपरहिट हॉरर-कॉमेडी भूत बंगला तक, प्रियदर्शन ने उनकी बेहतरीन काबिलियत का इस्तेमाल किया है। फिल्म का जॉनर चाहे जो भी हो, दोनों ने दर्शकों को हंसाने का सिलसिला जारी रखा।

वेलकम टू द जंगल में अक्षय और राजपाल दर्शकों को हंसा रहे हैं। जूम के साथ बातचीत में यादव ने इस मशहूर जोड़ी के बारे में प्रियदर्शन की कही बातें याद कीं। अक्षय के जुनून और लगन की तारीफ करते हुए, इस अनुभवी एक्टर ने उन्हें बॉलीवुड के इतिहास का सुनहरा सिक्का बताया।

राजपाल यादव ने कहा कि प्रियदर्शन ने अक्षय और राजपाल की जोड़ी को एक खास नाम दिया है। उन्होंने कहा प्रियदर्शन ने एक ऐसी लाइन बोली कि मैं उसके सामने नतमस्तक हो गया। वो बोले- इतनी फिल्में करने के बाद मैं अक्षय और

अक्षय कुमार की तारीफ में राजपाल ने पढ़े कसीदे



राजपाल को देखता हूँ तो टॉम एंड जेरी की याद आती है। अक्षय टॉम है, राजपाल जेरी है।

राजपाल यादव ने अक्षय कुमार की तारीफ करते हुए कहा मैं अक्षय

की इज्जत करता हूँ। उन्होंने प्रेरणा देने वाला काम किया है। अक्षय पा जी का कितना लंबा सफर है। अभी वेलकम टू द जंगल में भी, ऐसा लगता है कि किसी ने अभी काम

शुरू किया है। वह हर तरह के काम के लिए तैयार रहते हैं। हमारे बॉलीवुड में कितने चमत्कारी अजबूबे हैं, 100 साल की इंडस्ट्री में सुनहरे सिक्के हैं, अक्षय पा जी भी एक सुनहरे सिक्के हैं।

वेलकम टू द जंगल में अक्षय कुमार राजीव नाम के एक ऐसे एक्टर का रोल निभा रहे हैं, जो कभी स्टार हुआ करते थे लेकिन करियर में गिरावट के बाद अब उन्हें अपना स्टारडम बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। राजपाल एक ऐसे डायरेक्टर का रोल कर रहे हैं, जिन्हें फिल्म बनाने के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। इस फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान हैं।

मशहूर टीवी होस्ट और बॉलीवुड एक्टर मनीष पॉल की मां उर्मिल पॉल का 77 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। मनीष ने मां के निधन के बाद सोशल मीडिया पर एक बेहद ही इमोशनल पोस्ट साझा किया है। इसके साथ ही अभिनेता ने अपने प्रशंसकों से अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की है।

मां के जाने से दुखी मनीष पॉल ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। मनीष ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां के साथ कई तस्वीरें साझा की हैं। इसके साथ ही मनीष ने कैप्शन में लिखा, आज दुनिया कुछ ज्यादा खामोश है।

मनीष ने अपनी मां को याद करते हुए लिखा कि आज उन्होंने अपनी मां को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया

मां के निधन के बाद मनीष पॉल का छलका दर्द, कहा- आज दुनिया कुछ ज्यादा खामोश है



है। उन्होंने अपनी मां को अपना पहला घर, सबसे बड़ा सहारा और दुनिया की

सबसे मजबूत महिला बताया।

मनीष ने आगे लिखा, शब्द कभी यह नहीं बता सकते कि मेरी मां मेरे लिए क्या थीं और उनके जाने से ज़िंदगी में कितना बड़ा खालीपन आ गया है। हालांकि, मां का प्यार, उनकी ताकत, उनकी दयालुता और उनकी सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी। उम्मीद है कि अब आप सुकून में होंगी।

मनीष ने आगे लिखा, मां, मुझे उस तरह प्यार करने के लिए शुक्रिया, जैसा सिर्फ एक मां ही कर सकती है। जब तक फिर मुलाकात नहीं होती, हमेशा आपसे प्यार करता रहूंगा। मनीष पॉल

ने अपनी बचपन की दोस्त संयुक्ता पॉल से शादी की है। उनके दो बच्चे हैं- बेटी सायशा और बेटा युवान। मनीष ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में स्कूल और कॉलेज के प्रोग्राम्स में एंकरिंग से की थी। आज वह टीवी के सबसे लोकप्रिय होस्ट्स में से एक हैं। मनीष ने फिल्म मिक्की वायरस से बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में कदम रखा था। वह हाल ही में फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और अक्षय ओबेरॉय जैसे कलाकार भी थे।

अजब-गजब

भारत में है दुनिया का सबसे अमीर गांव

यहां घर-घर में एनआरआई, बैंकों में जमा हैं लोगों के 8000 करोड़ रुपये!

जब भी किसी गांव की बात होती है, तो ज्यादातर लोगों के मन में कच्ची सड़कें, खेती-किसानी और सीमित सुविधाओं वाली ज़िंदगी की तस्वीर आ जाती है। लेकिन आज हम आपकी गलतफहमी को दूर करने जा रहे हैं। दरअसल, भारत में एक ऐसा गांव भी है, जिसने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। यहां के लोगों के पास न सिर्फ शानदार पक्के घर हैं, बल्कि बैंक खातों में भी करोड़ों रुपये जमा हैं। यही वजह है कि इस गांव को दुनिया का सबसे अमीर गांव भी कहा जाता है। दरअसल, हम बात कर रहे हैं गुजरात के कच्छ जिले में स्थित माधापर गांव की। रेगिस्तान के करीब बसे इस गांव की अमीरी की चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में होती है।



मजबूत हैं कि उनके बैंक खातों में औसतन लाखों रुपये जमा हैं। सिर्फ बैंक ही नहीं, बल्कि गांव में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पार्क, झील, मंदिर और गौशाला जैसी सभी ज़रूरी सुविधाएं भी मौजूद हैं। यानी सुविधाओं के मामले में यह गांव कई शहरों को भी टक्कर देता है।

अब सवाल यह है कि आखिर माधापर दुनिया का सबसे अमीर गांव कैसे बन गया? इसकी सबसे बड़ी वजह यहां के लोगों का विदेशों से गहरा जुड़ाव है। करीब 80 हजार की आबादी वाले इस गांव के बड़ी संख्या में लोग कई दशक पहले रोजगार और कारोबार के लिए विदेश चले

गए थे। आज गांव के लगभग 65 प्रतिशत परिवारों का संबंध एनआरआई समुदाय से है। इनमें से कई लोग ब्रिटेन, अमेरिका, अफ्रीका और खाड़ी (गल्फ) देशों में रहते हैं। विदेश में रहकर ये लोग नियमित रूप से अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होती गई। इतना ही नहीं, कई एनआरआई सालों तक विदेश में सफल कारोबार करने के बाद वापस माधापर लौट आए। गांव लौटने के बाद उन्होंने यहां नए व्यवसाय शुरू किए और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए। यही कारण है कि आज माधापर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के सबसे अमीर गांवों में गिना जाता है। इस गांव के लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विदेश में रहने के बावजूद उन्होंने अपने गांव से रिश्ता नहीं छोड़ा। इसी सोच को मजबूत करने के लिए 1968 में लंदन में 'माधापर विलेज एसोसिएशन' की स्थापना की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य विदेश में रहने वाले गांव के लोगों को एक-दूसरे से जोड़कर रखना और अपने गांव के विकास में योगदान देना था। बाद में इसका एक कार्यालय माधापर में भी खोला गया, जिससे गांव और विदेश में रहने वाले लोगों के बीच संपर्क बना रहे।

मोनाको और इंडोनेशिया के झंडे हैं एक समान पहली नजर में लगते हैं दोनों बिल्कुल एक जैसे

दुनिया भर में 200 से ज्यादा देश हैं और हर देश का अपना अलग राष्ट्रीय झंडा है। ये झंडे देश की पहचान, इतिहास, संस्कृति और संघर्ष को दर्शाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दो ऐसे देश हैं जिनके झंडे देखकर कोई भी व्यक्ति पहली नजर में कन्फ्यूज हो सकता है? ये दोनों देश अलग-अलग महाद्वीपों में हैं, उनकी संस्कृति, भाषा और इतिहास अलग है, फिर भी उनके झंडे लगभग एक जैसे हैं। ये देश हैं: मोनाको और इंडोनेशिया। जहां मोनाको का झंडा दो क्षैतिज पट्टियों वाला है। ऊपरी पट्टी लाल और निचली पट्टी सफेद रंग की। इंडोनेशिया का झंडा भी ठीक वैसा ही है। ऊपर लाल और नीचे सफेद। दोनों में कोई प्रतीक, तारा, चांद या कोई अन्य निशान नहीं है। पहली नजर में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। दोनों झंडों में मुख्य अंतर उनके आकार में है। मोनाको का झंडा 4.5 के अनुपात का होता है, जबकि इंडोनेशिया का झंडा 2.3 के अनुपात का है। मतलब इंडोनेशिया का झंडा थोड़ा ज्यादा चौड़ा और लंबा दिखता है। लेकिन इतने सूक्ष्म अंतर को बिना मापे नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही वजह है कि लोग अक्सर दोनों को एक समझ बैठते हैं। मोनाको यूरोप के छोटे से देशों में से एक है, जो फ्रांस के दक्षिण में स्थित है। इसका झंडा 1881 में आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। लाल और सफेद रंग मोनाको के शासक परिवार ग्रिमाल्डी हाउस के रंग हैं। यह परिवार सदियों से मोनाको पर शासन कर रहा है। झंडे का डिजाइन प्राचीन समय से चला आ रहा है। मोनाको छोटा लेकिन अमीर देश है, जो अपनी लज्जरी, फैसीनी और टैक्स हेवन के लिए मशहूर है। वहीं इंडोनेशिया का झंडा मेराह पुति के नाम से जाना जाता है। यह 1945 में स्वतंत्रता मिलने के बाद आधिकारिक झंडा बना। लाल रंग बहादुरी और स्वतंत्रता के संघर्ष को दर्शाता है, जबकि सफेद रंग शुद्धता और न्याय का प्रतीक है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो देश है, जिसमें हजारों द्वीप हैं। इसका झंडा उच्च उपनिवेशवाद के खिलाफ लंबे संघर्ष की याद दिलाता है। दोनों देशों के झंडे समान होने का कोई सीधा संबंध नहीं है। यह संयोग माना जाता है। दोनों ने लाल और सफेद रंगों को चुना क्योंकि ये रंग कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण रहे हैं। यूरोपीय इतिहास में लाल-सफेद कई राजघरानों के रंग रहे, जबकि एशियाई देशों में ये स्वतंत्रता और शुद्धता के प्रतीक हैं। झंडा किसी देश की पहचान है। यह युद्ध के मैदान में, खेल प्रतियोगिताओं में और अंतरराष्ट्रीय समारोहों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। समान झंडे होने से कभी-कभी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यह भी विश्व की विविधता को दर्शाता है।



बंगाल में थम नहीं रहा सियासी बवाल

» पूर्व सीएम ने भाजपा पर किया प्रहार, बोलीं- मुझे चुप करवाना है तो मुझे मारना होगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी पर एक दूसरे पर हमला करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार टीएमसी नेताओं को परेशान कर रही है, लेकिन वह डरने वाली नहीं है। ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि अगर भाजपा उन्हें चुप कराना चाहती है तो उसे उनकी जान लेनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा उनकी आवाज दबाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी का यह वीडियो टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। वीडियो में ममता ने सीधे भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ने और नेताओं को डराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब टीएमसी छोड़कर गए तीन पूर्व सांसद भाजपा में शामिल हो चुके हैं और भाजपा ने उन्हें पश्चिम बंगाल के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार

भाजपा लगातार टीएमसी नेताओं को परेशान कर रही : ममता

कुछ लोग उनके साथ टीएमसी में रहने का दिखावा कर रहे हैं

ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर भी नाराजगी जारि की। उन्होंने कहा कि राजनीति में विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन कुछ नेता जनता के मते को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे

हैं, उन्हें साफ फैसला करना चाहिए या तो वे टीएमसी में रहकर पार्टी के साथ काम करें या फिर खुलकर भाजपा में शामिल हो जाएं। ममता बनर्जी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग टीएमसी में रहने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन काम

भाजपा के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी कार्यकर्ताओं को गुमराह करना बंद करना चाहिए। अगर कोई भाजपा में जाना चाहता है तो सीधे वहां चला जाए, लेकिन टीएमसी में रहकर भाजपा के लिए काम न करे।

भी बना दिया है। वीडियो में ममता बनर्जी ने कहा, कि अगर आपको मुझे चुप करवाना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा। तुमने इसके लिए

अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी को भी परेशान किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके घर तक पर हमला किया गया। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी जिक्र किया जो इस समय हिरासत में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकअप में उनके नेताओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ममता ने कहा कि कई लोगों



भाजपा ने तीनों बागियों को रास का बनाया उम्मीदवार



पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी को लगातार झटके लगा रहे हैं। पार्टी के कई सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता बागी गुट के साथ चले गए हैं। इसी बीच भाजपा ने 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए पूर्व टीएमसी सांसद सुजिता देव, सुखदेव शेखर रॉय और प्रकाश पिक बयडक को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये तीनों नेता हाल ही में टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मतदान और मतगणना दोनों उसी दिन होंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा इन सीटों पर भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है।

को जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कुछ लोगों की कमर में रस्सी बांधकर और पैरों में बेड़ियां लगाकर घुमाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ नेताओं का सिर मुंडवा दिया गया।

शिंदे व पवार की मुलाकात को पॉलिटिकल एंगल न दें: रोहित पवार

» विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात ने सियासी पारा गरमा दिया है। इस बीच शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा कि शरद पवार राजनीति से ऊपर हैं। पवार साहब जब आए तो एकनाथ शिंदे ने उनका सत्कार किया, वो उनका बड़प्पन है। पवार साहब को चलने में दिक्कत है, वहां जो सबसे नजदीकी दफ्तर था वो एकनाथ शिंदे का था इसलिए वहां पर बैठे थे, हम इसे राजनीति की परंपरा के नजरिए से सोच रहे हैं, उद्भव ठाकरे की पार्टी के नेता इसे पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं।



क्या पार्टी के सांसद असंतुष्ट हैं, इस सवाल पर उन्होंने कहा, विकास नहीं होने से असंतुष्ट होंगे ही। अयोध्या में जिस तरह से हुआ, हर एक मंदिर में ये चर्चा शुरू हो गई है। लोग बीजेपी और बीजेपी की विचारधारा जैसे पार्टी के खिलाफ जाने लगे हैं। इस स्थिति में हमारे सांसद और विधायक बीजेपी या बीजेपी के साथ वाले दूसरे पक्षों का सपोर्ट करेंगे, ऐसा तो हमको नहीं लगता। दरअसल, उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब शरद पवार के एनडीए में जाने की अटकलें भी लग रही हैं। वीर सावरकर को भारत रत्न देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, जब आएगा (प्रस्ताव) तब हम बात करेंगे। लेकिन हम सरकार से एक विनती करेंगे। सावरकर जी ने जो भी पुस्तक लिखी हैं, उसमें क्या-क्या लिखा है, वो पूरा चर्चा में आना चाहिए। उनका गाय के बारे में क्या मत था, धर्म के बारे में क्या मत था, देश और महिलाओं के बारे में क्या मत था, ये सारे विषयों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। जब चर्चा होगी तब लोगों को असलीयत का पता चलेगा। सावरकर जी की दो भूमिका है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक भी है। दोनों पहलू पर चर्चा होनी चाहिए। रोहित ने कहा हम महाराष्ट्र के हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं अब भी उसी तरह से डटे हैं।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सख्त

» अवैध हिरासत मानकर जांच के लिए आदेश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जबलपुर। कांग्रेस आईटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं को राजस्थान पुलिस द्वारा भोपाल साइबर क्राइम सेल के सहयोग से हिरासत में लेने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया को अवैध हिरासत माना है। हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस को पीड़ितों के बयान के आधार पर दर्ज एफआईआर की विधिवत जांच करने और राजस्थान पुलिस के संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच तार्किक निष्कर्ष तक जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का उद्देश्य काफी हद तक पूरा हो चुका है। इसी आधार पर अदालत ने याचिकाओं का निराकरण करते हुए जांच संबंधी जरूरी निर्देश जारी किए।

यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से वायरल हुए कथित फर्जी पत्र से जुड़ा है। इस मामले में राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े खिजर खान सहित तीन युवकों को हिरासत में लिया था। तीनों की ओर से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि उन्हें 19 अप्रैल की रात से 20 अप्रैल की रात और अगले दिन दोपहर तक भोपाल साइबर क्राइम थाने में अवैध रूप से रखा गया। इस दौरान उन्हें किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया।

भूपेंद्र को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए: जयराम

» पर्यावरण मंत्री के कार्यालय से चार कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय से चार सहयोगियों को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए जाने पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा है। पार्टी ने उनसे राजधर्म निभाने और नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग की है। पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे के ऐतिहासिक उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में मंत्रियों को राजनीतिक जवाबदेही तय करते हुए पद छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मंत्रालय में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है और शासन व्यवस्था चरमरा गई है।

जब किसी मंत्री के करीबी सहयोगियों को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया



जाता है, तो उन्हें पद छोड़ने पर विचार करना चाहिए और अपना राजधर्म निभाना चाहिए। पार्टी ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय से चार कर्मचारियों की बर्खास्तगी का उदाहरण देते हुए यह बात कही। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देते हुए सरकार पर निशाना साधा। रमेश ने एक्स पर कहा कि क्या भारतीय राजनीति में नैतिक

कांग्रेस नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी का भी किया जिक्र

कांग्रेस नेता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि अब अपना राजधर्म निभाने का समय आ गया है, जैसा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चौदह साल पहले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को याद दिलाया था। इस राजधर्म में नैतिक जिम्मेदारी और राजनीतिक जवाबदेही, दोनों शामिल हैं। कांग्रेस ने गुजरात को आरोप लगाया कि एक विशाल घोटाला हुआ है जिसके कारण ये बर्खास्तगी हुई है।

जिम्मेदारी का विचार अभी भी जिंदा है? लाल बहादुर शास्त्री ने तब सबसे ऊंचे मानक स्थापित किए थे, जब उन्होंने ठीक 70 साल पहले तमिलनाडु में हुए एक ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके उदाहरण को अवसर याद किया जाता है और उनकी बहुत तारीफ भी होती है, लेकिन शायद ही कभी किसी ने उनका अनुसरण किया हो।

श्रेयस की कप्तानी में लगातार दूसरी सीरीज हारा भारत

» भारत से पहली बार 2+ मैचों की टी20 सीरीज जीता इंग्लैंड

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

ब्रिस्टल। हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट के अर्धशतकों और दूसरे विकेट के लिए 146 रनों की अविजित साझेदारी के दम पर इंग्लैंड ने भारत को चौथे टी20 मैच में नौ विकेट से हराया। इंग्लैंड ने इसके साथ ही पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत को श्रेयस की कप्तानी में लगातार दूसरी सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले आयरलैंड ने भारत को 0-2 से मात दी थी। भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली।

श्रेयस के दौर की ये बेहद खराब शुरुआत है। पहले आयरलैंड और अब इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हार भारत के लिए काफी निराशाजनक है। 2019 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने लगातार दो टी20 सीरीज गंवाई है। इतना ही नहीं यह पहली बार है जब इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ दो या इससे ज्यादा मैचों की टी20 द्विपक्षीय सीरीज अपने नाम की है। दोनों टीमों के बीच इससे पहले छह में से पांच सीरीज भारत ने जीती थी,

जबकि एक सीरीज ड्रॉ रही थी। मौजूदा सीजन से पहले भारत ने पिछली 12 द्विपक्षीय सीरीज में से 11 अपने नाम की थी, जबकि दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। टी20 में गेंदें शेष रहते हुए भारत की यह तीसरी सबसे बड़ी हार है। वहीं, इंग्लैंड की भारत के खिलाफ टी20 में गेंदें शेष रहते हुए ये सबसे बड़ी जीत है। इंग्लैंड ने यह मैच 37 गेंदें शेष रहते हुए अपने नाम किया है। भारत को इस मामले में सबसे बड़ी हार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2008 में मिली थी, जब टीम इंडिया 52 गेंदें शेष रहते मुकाबला हार गई थी। वहीं, 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 40 गेंदें शेष रहते हुए हराया था।



100 टी20 मैच खेलने वाले पांचवें भारतीय बने अक्षर

ब्रिस्टल। अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गये चौथे टी20 मैच के दौरान अपने करियर की एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह बाएं हाथ का खिलाड़ी भारत के लिए 100 टी20 मैच खेलने वाला महज पांचवा क्रिकेटर बन गया है। इस खास वक्रे में वे रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और सुर्यकुमार यादव जैसे दिग्गजों के साथ शामिल हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अक्षर पहले भारतीय हैं जिन्होंने बिना कप्तानी के टी20 में भारत के लिए 100 मैच खेले हैं। हालांकि, वे कई द्विपक्षीय सीरीज और इसी साल घरेलू मैदान पर खेले गए टी20 विश्व कप 2026 के दौरान टीम के उपकप्तान रह चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी भी टीम की कप्तान संभालने का मौका नहीं मिला। अक्षर ने अपने 100 मैच पूरे किए, वहीं भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के नाम देश के लिए इस प्रारूप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। रोहित 159 मैचों के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इस उपलब्धि को हासिल करते ही अक्षर पटेल ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है। धोनी ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में भारत की ओर से 99 मुकाबले खेले थे।

गरीबों के पेट पर चलाया बुलडोजर! गोमती नगर जोन-4 में 12 ठेलियां तोड़े जाने पर उठे सवाल

भाजपा पार्षद के मुद्दा उठाने के बाद हुई कार्रवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क/मो.शारिक

लखनऊ। गोमती नगर विस्तार स्थित नगर निगम जोन-4 में 12 गरीब असामियों की ठेलियों को तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम की कार्रवाई ने उनकी रोजी-रोटी ही छीन ली।

कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा पार्षद संजय सिंह राठौर ने कथित अवैध ठेलियों का मुद्दा उठाया था, जिसका महापौर ने भी समर्थन किया। इसके बाद जोन-4 में कार्रवाई तेज हुई।



पीड़ितों का आरोप-नौकरी का झांसा देकर बुलाया और तोड़ दीं ठेलियां

आसामियों का आरोप है कि जोनल अधिकारी शिल्पा कुमारी की ओर से ठेली संचालकों को यह कहकर एलाएच कार्यालय बुलाया गया कि उनकी ठेलियों पर नंबर पेंट किए जाएंगे और उन्हें लखनऊ स्वच्छता अभियान से जोड़कर रोजगार दिया जाएगा। इस मरोसे में सभी अपनी ठेलियां लेकर पहुंचे, लेकिन

पीड़ितों का दावा है कि बाद में उन्हें 12 ठेलियों को बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि यही ठेलियां उनके परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र साधन थीं। अब उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है और परिवार के पालन-पोषण की चिंता सता रही है।

कैमरे से जोनल अधिकारी बचतीं नजर आईं

उधर, 4पीएम के कैमरे पर जोनल अधिकारी शिल्पा कुमारी ने विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज किया। उनका कहना था कि, आरोप लगते रहते हैं। ठेलियां अवैध थीं, इसलिए कार्रवाई की गई। अब बड़ा सवाल यह है कि यदि ठेलियां वास्तव में अवैध थीं, तो क्या उन्हें नियमानुसार जब्त कर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, या सीधे उन्हें तोड़ देना उचित था? क्या गरीब परिवारों की रोजी-रोटी पर इस तरह की कार्रवाई अंतिम विकल्प होनी चाहिये थी?

लंबे समय से डीपिंग प्वाइंट पर कूड़ा लाते थे कर्मि

मामले में यह सवाल भी उठ रहे हैं कि जिन लोगों की ठेलियां तोड़ी गईं, वे लंबे समय से दयाल चौराहे स्थित डीपिंग प्वाइंट पर कूड़ा लाते थे और कथित रूप से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण से जुड़े कार्य करते थे। इस व्यवस्था की जानकारी संबंधित एलाएच अधिकारियों को भी थी। यदि ऐसा था, तो बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उनकी ठेलियां तोड़ना उचित था?

राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सुप्रीम चौखट पर

सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को करेगा सुनवाई, याचिका में सीबीआई जांच की मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान की कथित चोरी पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सुर्य कांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। इस मुद्दे को लेकर कुल 3 याचिकाएं कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए लगेगी।

इन याचिकाओं में जांच सीबीआई को सौंपने और विशेष SIT के गठन के मांग की गई है। साथ ही, मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने किसी स्वतंत्र एजेंसी से ट्रस्ट का फॉरेंसिक ऑडिट कराने और मंदिर को मिल रहे दान की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव सार्वजनिक करने की भी मांग की है।

याचिकाकर्ताओं ने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की है। एक याचिका में भक्तों के सभी चढ़ावे को पवित्र ट्रस्ट की संपत्ति घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वज ट्रस्ट का पारदर्शी और भरोसेमंद प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश दे। अब इस मामले में सभी की नजर 13 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां अदालत इन मांगों और आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है।

तीन जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी

सुप्रीम कोर्ट के जिन 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी, उसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल हैं। जो 3 याचिकाएं कोर्ट में सुनवाई के लिए लगे जा रही हैं, उन्हें वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी, वकील अजय कुमार राय और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने दाखिल किया है।

राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों: वेणुगोपाल

कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल न्यायालय की देखरेख में जांच की मांग की

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

देहरादून। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे और दान की कथित चोरी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच उच्चतम न्यायालय की देखरेख में कराए जाने की मांग की है। उत्तराखंड के अपने दो दिवसीय दौरे के आखिरी दिन देहरादून में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वेणुगोपाल ने यह बात कही।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और उस सोने तथा पैसे को ट्रस्ट अथॉरिटी ने चोरी कर लिया। उन्होंने सवाल किया कि इस चंदा चोरी के लिए कौन जिम्मेदार है? वेणुगोपाल ने कहा कि चूंकि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में किया गया था, इसलिए प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए।

वेणुगोपाल ने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी इस कथित चोरी के मुद्दे को संसद में भी बड़े पैमाने पर उठाएगी। इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश अध्यक्ष गणेश

10 वर्षों में भाजपा सरकार उतराखंड में नहीं रोक पाई पलायन

वेणुगोपाल ने राज्य में बेरोजगारी और उससे होने वाले पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा बताया और आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं के अधिकारों के लिए लड़ेगी। इसके साथ ही, राज्य में चुनाव घोषणापत्र तैयार करने के लिए एक मैनीफेस्टो

कमेटी बनाई जाएगी जो युवाओं, छात्रों, किसानों और महिलाओं के पास जाकर उनकी समस्याएं टटोलेगी और एक जनपक्षीय घोषणापत्र तैयार करेगी।

गोदियाल भी उपस्थित थे। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए वेणुगोपाल ने बताया कि उन्होंने अपने दो दिवसीय दौरे में पार्टी की चुनावी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नेताओं, राजनीतिक मामलों की समिति, जिला कांग्रेस कमेटीयों के अध्यक्षों, विभिन्न विभागों, फंडल संगठनों और वर्तमान व पूर्व विधायकों के साथ बैठकें कीं। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य में पार्टी संगठन और सभी नेता पूरी एकजुटता और ताकत के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। नेताओं से चर्चा के बाद वेणुगोपाल ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों की भाजपा सरकार से जनता में भारी निराशा है और लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ हैं। कांग्रेस इस माहौल का लाभ उठाकर जीत दर्ज करने के लिए पूरा जोर लगाएगी।

करूर भगदड़ पर डीएमके कर रही है राजनीति: सीएम विजय

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने द्रमुक और पुलिस पर साधा निशाना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को द्रविड़ मुनेत्र कषमम (द्रमुक) पर करूर में पिछले वर्ष हुई भगदड़ की दुखद घटना से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उस समय उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जिले का दौरा करने से भी रोका गया था। पिछले साल हुई इस घटना के बाद पहली बार करूर पहुंचे मुख्यमंत्री ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए।

मुख्यमंत्री विजय ने पुलिस की आलोचना करते हुए कहा कि 27 सितंबर

को तमिलनाडु वेत्ती कषमम (टीवीके) की सभा के दौरान पुलिस ने उन्हें लगातार बढ़ रही भीड़ के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी। उन्होंने कहा कि भीड़ के अनियंत्रित होने के बावजूद पुलिस ने सभा को रद्द करने का कोई कदम नहीं उठाया, जबकि पुलिस के पास ऐसा करने का पूरा अधिकार था। इसके बजाय पुलिस उन्हें अपनी सुरक्षा में सीधे राजमार्ग तक ले गई। मई में मुख्यमंत्री पद संभालने वाले विजय ने बताया कि वह 25 में करूर जाकर इस हादसे से प्रभावित हुए 41 पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सके थे। हालांकि, बाद में उन परिवारों को चेन्नई के समीप लाया गया था, जहां उन्होंने खुद मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को भेजा जेल

चेक बाउंस केस में फैसला जुरमाना भी लगा, कहां-एक्टर का व्यवहार संदिग्ध

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस केस में उन्हें 3 महीने जेल की सजा सुनाई है। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक्टर पर जुरमाना भी लगाया है। साथ ही सजा बरकरार रखते हुए राजपाल यादव के व्यवहार को संदिग्ध बताया और अधिकारियों से उन्हें वापस जेल भेजने को कहा।

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को अदालत ने चेक बाउंस मामले में उनकी सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें फिर से जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में



एक्टर का रवैया संदिग्ध रहा है। इससे पहले अप्रैल 21०8 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा को दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2०१9 में सेशन कोर्ट ने भी इस फैसले को सही माना। फिर एक्टर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जून 2०24 में हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगाई थी और बकाया करीब 9 करोड़ रुपये चुकाने के लिए

मामला साल 2010 का है पांच करोड़ का लिया था कर्ज

यह मामला साल 2०1० का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी और इसके बाद वह तय समय पर कर्ज नहीं चुका पाए। इसी वजह से मामला अदालत तक पहुंच गया।

उन्हें ईमानदारी से प्रयास करने का मौका दिया था। लेकिन अदालत के मुताबिक, राजपाल यादव बार-बार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहे। इसी वजह से इस साल 2 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था और अब उनकी सजा को भी बरकरार रखा गया है।